



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 958 राँची, सोमवार, 20 अग्रहायण, 1939 (श०)  
11 दिसम्बर, 2017 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

9 अक्टूबर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक-1222/गो० दिनांक 10 अप्रैल, 2010 एवं पत्रांक- 3506/गो० दिनांक 2 दिसम्बर, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-3080 दिनांक 8 जून, 2011

**संख्या- 5/आरोप-1-510/2014 का.-10455--** श्री प्रदीप प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-664/03, गृह जिला-देवघर), अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के विरुद्ध इनके अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1222/गो० दिनांक 10 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1640, दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा लघु शास्तियाँ के अन्तर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:-

1. चार वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव रोक एवं
2. निन्दन

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका W.P.(S) No.-4548/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 को पारित आदेश में श्री प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त किया गया है। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है:-

**5(iii)-** In the instant case, after acceptance of the explanation by the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa, there was no occasion on the part of respondent no.-2 to differ with the opinion of the Deputy Commissioner. However, no show cause was issued prior to imposition of punishment which has prevented the petitioner to make an effective representation as envisaged under Rule 55(A) of Civil Services Rules.

**6-** On the cumulative effect of facts and reasons stated in the foregoing paragraphs, the impugned order of punishment dated 20 February, 2013 being not legally sustainable is, hereby, quashed and set aside.

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं०-7166, दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड से संबंधित संकल्प सं०-1640, दिनांक 20 फरवरी, 2013 को निरस्त कर दिया गया तथा विभागीय पत्रांक-7428, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

श्री प्रसाद द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 5823/2016 with Cont. Case (Civil) No. 553/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2017 को आदेश पारित कर द्वितीय कारण पृच्छा को निरस्त कर दिया है। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है-

".... This Court is inclined to exercise the judicial review by quashing impugned show cause notice dated 27 August, 2016 vide annexure-8 to the writ petition.

Resultantly, the writ petition stands allowed.

In view of disposal of the writ petition and on perusal of the show cause filed on behalf of opposite party nos. 1 and 2, Cont. Case (Civil) No. 553 of 2016 is hereby dropped."

अतः समीक्षोपरांत उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद से पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा को निरस्त करते हुए संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सूर्य प्रकाश,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----